भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3931
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद
3931. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कुल कृषि उपज का कितना प्रतिशत वास्तव में एमएसपी पर खरीदा जाता है तथा इसका क्या कारण है कि अभी भी कई किसानों को अपनी फसलें एमएसपी से कम पर बेचनी पड़ती हैं; और
(ख) उन राज्यों में खरीद बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां किसान एमएसपी पर अपनी उपज बेचने के लिए संघर्ष करते हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

सरकार, किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। जब कभी भी दलहनों, तिलहनों और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहनों, तिलहनों और कोपरा की खरीद की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां हैं। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी एमएसपी पर क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से की जाती है।

सरकार की मूल्य नीति, एमएसपी पर उनकी उपज की खरीद के प्रस्ताव के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराती है। तथापि, किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान खरीफ फसलें, रबी फसलें और पटसन एवं कोपरा की खरीद और उसका प्रतिशत संबंधी विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

खरीफ, रबी तथा पटसन एवं कोपरा की खरीद का विवरण

(आंकड़े एलएमटी में)

क्र.सं.	**फसल**	**खरीद (2023-24)**	**कुल खरीद की तुलना में फसल-वार खरीद का प्रतिशत**
1.	खरीफ फसलें	805.34	73.95
2.	रबी फसलें	281.05	25.81
3.	अन्य फसलें	2.66	0.24
	कुल	**1089.05**	**100.00**

सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर प्रभावी खरीद करने और किसानों को एमएसपी का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक्स/इनफ्रास्ट्रक्चर जैसे भंडारण और परिवहन आदि की उपलब्धता के मद्देनजर संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे नेफेड, एनसीसीएफ, एफसीआई आदि द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए विद्यमान मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

*****